"News Clips"

Job Oriented Training for Minorities Affairs Department in Rajasthan
(Government of Rajasthan & CIDC Joint initiative)

Move okayed to train minority youths

DNA Correspondent

Chief minister Ashok Gehlot on Thursday approved a proposal for minorities affairs department to provide training to the candidates belonging to the minority community to enable them to get employment. Training will be provided by the Construction Industry Development Council (CIDC)- a government of India enterprise, which will benefit almost 1,000 candidates and will cost ₹1 crore to the state government.

Rajasthan state scouts and guide will organise a tree plantation programme project on July 11 – DNA

Aid to minority

- Training will be provided by the Construction Industry Development Council, a government of India enterprise which will benefit almost 1,000 candidates and cost ₹1 crore to the state government
- Apart from this, 500 candidates will be provided training by Rajasthan Ajivika Mission Nirman Akademy which will also bear the expenses of this training programme

RAJASTHAN ROUND-UP

Apart from this, 500 candidates will be provided training by Rajasthan Ajivika Mission Nirman Akademy which will also bear the expenses of this training programme. The training programme will last for 2-3 months. Gehlot also approved a proposal to establish village court (gram nyayalaya) in village Kurli in Sikar district.

TREE PLANTATION DRIVE

Rajasthan state scouts and guide will be organising a tree plantation programme under the environment awareness project on July 11. The programme will start at 11 in the morning and about 11 lakh plants will be planted under the programme.

Industries minister Rajendra Pareek while releasing a poster on 'go -green drive' in the secretariat commended the scouts and guide for their efforts towards plantation drive.

State chief commissioner of scouts and guide Niranjan Arya who was also present on the occasion informed that 11 lakh plants will be planted at 11,000 selected places including schools at one go.

He added that to ensure smooth functioning of the plantation drive, the responsibility has been given to 5 lakh scouts and guides and also to rovers and rangers who will have to ensure planting of two plants each.

STAMP ON KOTHARI

The Department of Posts on Thursday issued a commemorative postage stamp on Dr Daulat Singh Kothari. Born in Udaipur, Kothari (1906-1993) was an eminent Indian scientist. He had his early education in Udaipur and Indore and did MSc in physics from the Allahabad University in 1928 under the guidance of great physicist Meghnad Saha.

Kothari worked in Delhi University from 1934 to 1961 in various capacities as reader, professor and head of the physics department.

अल्पसंख्यक वर्ग के डेढ़ हजार युवाओं को देंगे प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाने की योजना है।

प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी.आई.डी.सी.) के माध्यम से जिलास्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें एक हजार अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। इस पर राज्य सरकार एक करोड़ रुपए व्यय करेगी। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय को राजस्थान आजीविका मिशन उठायेगा। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में अल्पसंख्यक वर्ग के युवकों को आई.सी.आई. अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। प्रशिक्षण अवधि दो से तीन माह की होगी।

कुड़ली में ग्राम न्यायालय स्थापित

: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले के कुड़ली में ग्राम न्यायालय सृजित एवं स्थापित करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने 18 दिसंबर 2009 को जारी अधिसूचना के द्वारा प्रदेश में 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में प्रदेश में 45 ग्राम

पिंकसिटी न्यूज...

अल्पसंख्यक वर्ग के डेढ़ हजार युवकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाये जाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी.आई.डी.सी.) के माध्यम से जिलास्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें एक हजार अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे तथा इस पर राज्य सरकार एक करोड़ रूपये व्यय करेगी। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय को राजस्थान आजीविका ...। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में ... के युवकों को आई.सी.आई. अकादमियों के माध्यम ... की घोषणा की थी। प्रशिक्षण अवधि दो से तीन माह

डेढ़ हजार अल्पसंख्यक युवकों को मिलेगा प्रशिक्षण

जयपुर, 7 जुलाई (कासं)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाए जाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी.आई.डी.सी.) के माध्यम से जिलास्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें एक हजार अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे तथा इस पर राज्य सरकार एक करोड़ रूपए व्यय करेगी। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 अयर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पर होने वाले व्यय को राजस्थान आजीविका मिशन ही उठाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में अल्पसंख्यक वर्ग के युवकों को आईसीआई अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। प्रशिक्षण अवधि दो से तीन माह की होगी।

आवासनियों को नि:शुल्क चिकित्सा

जयपुर, 7 जुलाई। ...

अल्पसंख्यक युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

कुंडली में ग्राम न्यायालय खुलेगा

अल्पसंख्यक वर्ग के डेढ़ हजार युवकों को प्रशिक्षण मिलेगा

जयपुर, (कासं): मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाए जाने की योजना है।

प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के जरिए जिला स्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें एक हजार अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार इस पर एक करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पर होने वाले व्यय को राजस्थान आजीविका मिशन ही उठाएगा। प्रशिक्षण अवधि दो से तीन माह की होगी।

अल्पसंयक वर्ग के डेढ़ हजार युवकों को प्रशिक्षण

जयपुर, 7 जुलाई (कासं)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंयक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंयक वर्ग के अयर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाये जाने की योजना है।

प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी.आई.डी.सी.) के माध्यम से जिलास्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें एक हजार अयर्थी लाभान्वित होंगे तथा इस पर राज्य सरकार एक करोड़ रूपये व्यय करेगी। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 अयर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय को राजस्थान आजीविका मिशन ही उठायेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में अल्पसंयक वर्ग के युवकों को आई.सी.आई. अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। प्रशिक्षण अवधि दो से तीन माह की होगी।

अल्पसंख्यक युवकों को मिलेगा प्रशिक्षण

जयपुर . अल्पसंख्यक वर्ग के डेढ़ हजार युवकों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। युवकों को केन्द्र सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी.आई.डी.सी.) के माध्यम से जिलास्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसमें एक हजार अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

CIDC to begin skill development of minority youth

BK Jha
htraj@hindustantimes.com

JAIPUR: The Construction Industry Development Council (CIDC), set up by the Planning Commission, is all set to take up large scale skill development and training programmes for construction sector.

The chief minister on Thursday had approved a proposal of minority affairs department to provide training to the candidates belonging to the minority community to enable them to get employment.

The chief minister had announced in his budget speech this year that the minority youths would be trained professionally by prominent human resource development institutions.In view of the announcement minority affairs depart- training programme. Now, CIDC will train around 1000 candidates and the programme will cost the state government R 1 crore.

"We appreciate swift action taken by the government and will soon take up the training programme. Moreover, we have also proposed the government to train 20000 construction workers annually," PR Swarup, director general, CIDC told Hindustan Times.

"The draft proposal is being vetted by the CS who is also the chairman of Rajasthan Mission on Skill and Livelihoods (RMoL),a government wing for skill development," he added.

The director general said the CIDC has also offered its training services to Panchayati Raj department, which spends nearly ₹17000 crore under NREGA

डेढ़ हजार युवको को प्रशिक्षण दिया जायेगा

जयपुर, 7 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाये जाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद के माध्यम से जिला स्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें एकं हजार अभ्यर्थी लाभन्वित होंगे तथा इस पर राज्य सरकार एक करोड़ रुपए व्यय करेगी। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय को राजस्थान आजीविका मिशन ही उठायेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में अल्पसंख्यक वर्ग के युवकों को आईसीआई अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी।

1500 अल्पसंख्यक युवकों को मिलेगा प्रशिक्षण

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के माध्यम से जिलास्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 1000 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। सरकार इस पर 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही, राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

70 लाख बच्चों को मिलेगी वर्क बुक

डेढ़ हजार अल्प संख्यक युवकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाये जाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार की संस्था निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के माध्यम से जिला स्तर पर 13 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें एक हजार अभ्यार्थी लाभान्वित होंगे तथा इस पर राज्य सरकार एक करोड़ रुपये व्यय करेगी। इसके साथ ही राजस्थान आजीविका मिशन निर्माण अकादमी के माध्यम से संभाग स्तर पर 500 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय को राजस्थान आजीविका मिशन ही उठायेगा।